दैनिक
उत्तराखण्ड प्रहरी
उत्तराखण्ड का सबसे विश्वसनीय मीडिया पार्टनर

वर्ष 15 /अंक 62 / पृष्ठ 8
हरिद्वार, सोमवार, 01 मई 2023
uttarakhandprahari19@gmail.com | e-paper: uttarakhandprahari.com
RNI No. : - UTTHIN/2009/27592
मूल्य- 2 रु.

मजबूत डिजिटल ढांचे की अहमियत
प्रदेशभर में सुना गया प्रधानमंत्री के 'मन की बात' ...

मुंबई में मन की बात की 100वीं कड़ी का 5,000 जगहों पर प्रसारण

मुंबई, (भाषा)। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में रविवार को कई जगहों पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' की 100वीं कड़ी का प्रसारण किया गया, जिनमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की मुंबई इकाई ने रविवार को शहर और उपनगरों के 36 विधानसभा क्षेत्रों में 5,000 जगहों पर 'मन की बात' की 100वीं कड़ी के प्रसारण की व्यवस्था की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में एक स्थान पर आयोजित प्रसारण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के 'मन की बात' सुनी। निजी दौरे पर मुंबई पहुंचे शाह ने उपनगरीय विले पार्ले में आयोजित प्रसारण कार्यक्रम में हिस्सा लिया और फिर कांदिवली के लिए रवाना हुए। उत्तर-मध्य मुंबई से भाजपा सांसद पूनम महाजन और स्थानीय विधायक पराग अलवानी भी शाह के साथ कार्यक्रम में उपस्थित थे। वहीं भाजपा की मुंबई इकाई के अध्यक्ष आशीष शेलार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 'मन की बात'

कार्यक्रम के जरिये नागरिकों से लगातार संवाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक सर्वेक्षण के अनुसार, यह कार्यक्रम लगभग 100 करोड़ श्रोताओं तक पहुंच गया है और इसके लगभग 23 करोड़ नियमित श्रोता हैं। इस बीच राजभवन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' की 100वीं कड़ी के प्रसारण के मौके पर महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने कहा, "स्वामी विवेकानंद की तरह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने 'मन की बात' संबोधन के माध्यम से भारत के प्रति दुनिया की धारणा को बदल दिया है।" बैस ने कहा कि भारत के लोग अब अपने भारतीय होने पर गर्व महसूस करते हैं।

इस अवसर पर पद्म पुरस्कार विजेता पोपटराव पवार, मिलिंद कांबले, डॉ शशांक जोशी, डॉ कीकी मेहता और 'मन की बात' के विभिन्न कड़ी में उल्लेखित अन्य लोग भी उपस्थित थे। फिल्म उद्योग का प्रतिनिधित्व अभिनेत्री माधुरी दीक्षित, शाहिद कपूर, शैलेश लोढ़ा, प्रसाद ओक, प्रसिद्ध गायिका अनुराधा पौडवाल, सोनू निगम, फिल्म निर्माता एकता कपूर, रोहित शेट्टी सहित अन्य ने किया।

जो देशवासी मेरा सब कुछ हैं, मैं उनसे ही कटकर जी नहीं सकता था। मन की बात ने मुझे इस चुनौती का समाधान दिया। आम लोगों से जुडने का रास्ता दिया। इस कार्यक्रम ने मुझे कभी भी आपसे दूर नहीं होने दिया। मोदी ने कहा, मन की बात ने मुझे लोगों से जुडने का जरिया मुहैया कराया। यह मेरे लिए महज एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है।

प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने तीन अक्टूबर 2014 को मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसके माध्यम से वह हर महीने के आखिरी रविवार को विभिन्न मुद्दों पर लोगों के साथ अपने विचार साझा करते हैं। मन की बात के लिए श्रोताओं से राष्ट्रीय महत्व से जुड़े मुद्दों पर सुझाव और विचार भी आमंत्रित किए जाते हैं। कार्यक्रम की 100वीं कड़ी से पहले प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि मन की बात कार्यक्रम उनके लिए एक विशेष यात्रा रहा है।

बसपा ने नगर निगम चुनावों में मुसलमानों को उचित भागीदारी देकर सांप्रदायिक दलों की नींद उड़ाई:मायावती

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी द्वारा नगर निगम चुनावों में मुस्लिम समाज को उचित भागीदारी दिए जाने के कारण जातिवादी एवं साम्प्रदायिक दलों की नींद उड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में चार मई और 11 मई को नगर निकाय चुनाव होने हैं और मतगणना 13 मई को की जाएगी। बसपा प्रमुख ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के तहत 17 नगर निगमों में महापौर पद के लिए हो रहे चुनाव में बसपा द्वारा मुस्लिम समाज को भी उचित भागीदारी देने को लेकर यहां राजनीति काफी गरमाई हुई है और इससे खासकर जातिवादी एवं साम्प्रदायिक दलों की नींद उड़ी हुई है। मायावती ने कहा, बसपा सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीति व सिद्धांत पर चलने वाली आंबेडकरवादी पार्टी है तथा इसने इसी आधार पर उत्तर प्रदेश में चार बार अपनी सरकार चलाई।

पंजाब के लुधियाना में गैस रिसाव से 11 लोगों की मौत : पुलिस

लुधियाना। पंजाब में लुधियाना जिले के घनी आबादी वाले ग्यासपुरा इलाके में रविवार को जहरीली गैस के रिसाव के कारण 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग बीमार पड़ गए। पुलिस ने बताया कि बीमार लोगों का एक अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किस गैस का रिसाव हुआ और इसका क्या कारण था, यह फिलहाल पता नहीं लगाया जा सका है। बहरहाल, लुधियाना की उपायुक्त सुरभि मलिक ने बताया कि ऐसी आशंका है कि सीवर में कुछ रसायनों की मीथेन गैस से प्रतिक्रिया हुई होगी। उन्होंने बताया कि इलाके को खाली करा लिया गया है और गैस के फैलने पर रिसाव स्थल की घेराबंदी का दायरा बढ़ाया जाएगा।

उपायुक्त ने बताया कि घटना में जान गंवाने वाले लोगों में श्वसन संबंधी समस्या का कोई लक्षण नहीं दिखा। उन्होंने कहा, ऐसी आशंका है कि न्यूरोटॉक्सिन (विषाक्त पदार्थ के संपर्क में आने से तंत्रिका तंत्र की सामान्य गतिविधि में बदलाव) की वजह से मौत हुई है। जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि घटनास्थल पर पहुंची राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की टीम यह पता लगाएगी कि किस गैस का रिसाव हुआ और इसका स्रोत एवं कारण क्या था। उन्होंने कहा कि चूंकि, यह बेहद घनी आबादी वाला इलाका है, इसलिए तत्काल प्राथमिकता लोगों को वहां से सुरक्षित निकालना थी। लुधियाना की उपायुक्त ने बताया कि एनडीआरएफ का एक दल विभिन्न तरह के रसायनों के नमूने एकत्रित कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब रासायनिक प्रक्रिया के बारे में पता चल जाएगा तो जानकारियां साझा की जाएगी। पुलिस ने इलाके को सील कर दिया है और वहां राहत एवं बचाव कार्यों के लिए एक दमकल वाहन और एक एम्बुलेंस को तैनात किया गया है।

तेलंगाना को मिला नया सचिवालय; सीएम चंद्रशेखर ने किया उद्घाटन, डा. बीआर अंबेडकर सचिवालय दिया नाम

हैदराबाद। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने रविवार को तेलंगाना सचिवालय का उद्घाटन करते हुए कहा कि यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि आज मेरे हाथों से एक प्रशासनिक केंद्र के रूप में सचिवालय का उद्घाटन किया जा रहा है। यह शानदार ढंग से बनाया गया है। सचिवालय का नाम बीआर अंबेडकर सचिवालय रखा गया है। हैदराबाद तेजी से अंतरराष्ट्रीय शहर बनता जा रहा है। यह हर प्रकार की सुविधाओं, कई फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, अंडरपास से युक्त है, यह भव्य पुनर्निर्माण है। हर तरफ सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, वारंगल हेल्थ सिटी विकसित हो रहा है, यह तेलंगाना के नवनिर्माण का प्रतीक हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी के संघर्ष के बाद तेलंगाना राज्य का सपना साकार हुआ है। भारत को गौरवान्वित करने के लिए राज्य सचिवालय का नाम बीआर अंबेडकर सचिवालय रखा है। सीएम केसीआर ने कहा कि तेलंगाना कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। हम एकीकृत विकास के साथ कृषक समुदाय के कल्याण के अलावा औद्योगिक नीति में लाखों करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने वाले राज्य के रूप में देश में शीर्ष पर हैं।

तेलंगाना औद्योगिक नीति और आईटी नीति में बंगलुरु से आगे बढ़ रहा है। तेलंगाना में जनता बिना मामूली सांप्रदायिक दंगे के दस साल सुरक्षा पूर्वक रह रही है। तेलंगाना पुलिस देश की अग्रणी पुलिस बन गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यादाद्री मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया है, यहां से तेलंगानावासियों को दोनों हाथों से आशीर्वाद मिल रहा है। तेलंगाना का पुनर्निर्माण देश और दुनिया के लिए आदर्श है। धूप में फाइलें लिए आड़े तिरछे चलने वाले और बरसात में फाइलों को पकडकर इधर-उधर भागने की स्थितियों से बचाने के लिए नए वैभव के साथ तेलंगाना सचिवालय का निर्माण हुआ है।

आवश्यक सूचना

'उत्तराखंड प्रहरी' के सभी पाठकों को सूचित किया जाता है कि आप अपने प्रिय अखबार 'उत्तराखंड प्रहरी' महाभियान में शामिल हो सकते हैं। आप अपने द्वारा लिखी गई कोई भी संरचना, कविता, कहानी, लेख या कार्यक्रम हमसे साझा कर सकते हैं। अच्छे लेख व कहानी को 'उत्तराखंड प्रहरी' में उचित स्थान दिया जाएगा। आप अपने प्रियजनों को जन्मदिन, सालगिरह या अन्य शुभ अवसरों पर बधाई संदेश भी दे सकते हैं।

आप हमें ईमेल
uttarakhandprahari19@gmail.com या
whatsup no 8077771906 पर भी भेज सकते हैं।

संपादकीय

चुनाव आया, ज़हर लाया

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े ने एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री को 'ज़हरीला सांप' करार दिया है और कहा है कि यदि आप इसका विष चखेंगे, तो आपकी मृत्यु हो जाएगी।' खडग़े ने बाद में सफाई भी दी कि उन्होंने प्रधानमंत्री की विचारधारा को 'सांप' कहा है। यदि फिर भी किसी को ठेस पहुंची है, तो उन्हें खेद है। यह प्रवृत्ति किसी को मार कर पुचकारने वाली है। कांग्रेस की गाली देने और अपमानित करने की परंपरा पुरानी है। मार्च, 2023 में ही कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को 'तानाशाह' कहा था। उससे पहले गुजरात चुनाव के दौरान नफरती अंदाज़ में खडग़े ने कहा था कि मोदी '10 सिर वाला रावण' है क्या? वह प्रधानमंत्री मोदी को 'झूठों का सरदार' तो कई बार कह चुके हैं। 2014 में नरेन्द्र मोदी देश के प्रधानमंत्री चुने ही गए थे कि एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने उन्हें 'सांप' कहा था।

कई कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री के लिए अभद्र, अश्लील, गरिमाहीन और मर्यादाहीन अपशब्दों का प्रयोग किया है। हम बार-बार विश्लेषण कर चुके हैं कि यह अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। शब्दों, भाषा और जुबान का संयम तो रहना ही चाहिए। प्रधानमंत्री ने भी कुछ आपत्तिजनक विशेषणों का प्रयोग किया था, लेकिन वे चुनाव तक ही सीमित रहे। अलबत्ता वे गाली के स्तर के शब्द नहीं थे। वे व्यंग्यात्मक जरूर थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने उन शब्दों को दोहराया नहीं है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति इसे 'नफरती एजेंडा' ही तय कर लिया है। राजनीति प्रतिशोध से नहीं की जा सकती। यह लोकतंत्र का अवमूल्यन है। कांग्रेस अध्यक्ष खडग़े ने कर्नाटक चुनाव के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री की तुलना 'ज़हरीले सांप' से की। क्या इसी आधार पर चुनाव लडक़र कांग्रेस जीतना और सत्ता हासिल करना चाहती है? प्रधानमंत्री मोदी भी 142 करोड़ से अधिक की आबादी के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। क्या जनता ने 'ज़हरीले सांप' को जनादेश दिया था? क्या प्रधानमंत्री को गाली देने के मायने देश की जनता और लोकतंत्र को अपशब्द कहना नहीं हैं? क्या लोकतंत्र और संविधान में ऐसी गालियों की कोई गुंज़ाइश है? हम लगातार देख रहे हैं कि जब भी चुनाव आता है, तो कांग्रेस अध्यक्ष समेत पार्टी के नेता और प्रवक्ता ज़हर उगलना शुरू कर देते हैं। यह उनकी राजनीतिक कुंठा भी हो सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री एवं मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी को 'मौत का सौदागर' कहकर गाली दी थी। पूरा चुनाव साफ हो गया। 'खून की दलाली' और 'ज़हर की खेती' तक भी कहा गया। पार्टी प्रमुख के तौर पर ही राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव का पूरा अभियान इसी नारे पर चलाया-'चौकीदार चोर है।' प्रधानमंत्री मोदी खुद को देश का 'चौकीदार' और 'प्रधान सेवक' मानते रहे हैं। इन नेताओं के अलावा मणिशंकर अय्यर, जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी, शशि थरूर, सुबोधकांत सहाय, संजय निरुपम, रेणुका अय्यर सरीखों की लंबी फेहरिस्त है, जिन्होंने प्रधानमंत्री के लिए नफरती और ज़हर-बुझे शब्दों का लगातार इस्तेमाल किया है। नतीजा यह रहा कि कांग्रेस लगातार पराजित हो रही है। कुछ राज्यों में सरकारें हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो इसी साल चुनाव होने हैं। कर्नाटक बेहद संवेदनशील राज्य है। यदि यहां कांग्रेस चुनाव जीतने में नाकाम रही, तो देश भर में 'अप्रासंगिक' हो जाएगी। सवाल यह है कि क्या कर्नाटक की गुत्थियां और समस्याएं प्रधानमंत्री को गाली देने से हल हो सकती हैं? लोकसभा में कांग्रेस के इतने सांसद भी नहीं हैं कि कांग्रेस संसदीय दल के नेता को 'प्रतिपक्ष के नेता' का दर्जा दिया जा सकता।

मजबूत डिजिटल ढांचे की अहमियत

डा. जयंतीलाल भंडारी

इन दिनों देश और दुनिया के विभिन्न प्रमुख आर्थिक और वित्तीय संगठनों की रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि भारत में डिजिटलीकरण से आर्थिक कल्याण और अर्थव्यवस्था के विकास का नया दौर दिखाई दे रहा है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के द्वारा प्रकाशित वर्किंग पेपर 'स्टैकिंग अप द बेनेफिट्स लेसन्स फ्रॉम इंडियाज डिजिटल जर्नी' में कहा गया है कि डिजिटलीकरण ने भारत की अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने में मदद की है और आधार ने लीकेज को कम करते हुए लाभार्थियों को भुगतान के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर डीबीटी) में मदद की है। साथ ही मार्च 2021 तक डिजिटल बुनियादी ढांचे और अन्य डिजिटल सुधारों के कारण व्यय में जीडीपी का लगभग 1.1 फीसदी बचाया गया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) की सराहना दुनिया भर में की जा रही है। इस समय देश में करीब 47.8 करोड़ से अधिक जनधन खातों, (जे) करीब 134 करोड़ से अधिक आधार कार्ड (ए) और 118 करोड़ से अधिक मोबाइल उपभोक्ताओं (एम) के तीन आयामी जैम से आम आदमी डिजिटल दुनिया से जुड़ गया है। भारत में वर्ष 2014 से लागू की गई डीबीटी योजना एक वरदान की तरह दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से डिजिटल समानता से समाज के सभी वर्गों की पहुंच डिजिटल प्रौद्योगिकी की ओर बढ़ गई है। भारत में डीबीटी से कल्याणकारी योजनाओं के जरिए महिलाओं, बुजुर्गों और किसानों और कमजोर वर्ग के लोगों को अकल्पनीय फायदा हो रहा है। उल्लेखनीय है कि 3 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीआई के डायमंड जुबली समारोह में कहा कि सरकार ने वर्ष 2014 से लेकर अब तक डीबीटी के जरिए करीब 27 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि सीधे लाभान्वितों के बैंक खातों तक पहुंचाई गई है। केंद्र सरकार के द्वारा गरीबों, किसानों और कमजोर वर्ग के करोड़ों लोगों के बैंक खातों में डीबीटी से सीधे सब्सिडी जमा कराए जाने से करीब सवा दो लाख करोड़ रुपए बिचौलियों के हाथों में जाने से बचाए गए हैं।

निसंदेह भारत ने पिछले एक दशक में मजबूत डिजिटल ढांचे से डिजिटलीकरण में एक लंबा सफर तय कर लिया है। सरकारी योजनाओं के तहत बिचौलियों के भ्रष्टाचार को रोकने, काम के भौतिक रूपों व सरकारी कार्यालयों में लंबी कतारों से राहत और घरों में आराम से मोबाइल स्क्रीन पर कुछ क्लिक करके विभिन्न सेवाओं, सुविधाओं और मनोरंजन की सहज उपलब्ध सुविधाएं हैं। ज्ञातव्य है कि जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की 450 से अधिक सरकारी योजनाओं का फायदा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाने में बड़ी कामयाबी मिली है, वहीं लोगों की सुविधाएं बढ़ी हैं। देश में सौ से अधिक सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। पहले बैंक, गैस, स्कूल, टोल, राशन हर जगह कतारें होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सरकारी दफ्तर आपकी मुठ्ठियों में रखें मोबाइल तक पहुंच गए हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है कि छोटे उद्योग, कारोबार के लिए सरल ऋण और रोजगार सृजन हेतु अप्रैल 2015 को डिजिटल रूप से लागू प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मार्च 2023 तक 40.82 करोड़ लोन खातों में 23.2 लाख करोड़ रुपए पहुंचाए गए हैं। इसी तरह अटल पेंशन योजना, भारत बिल भुगतान प्रणाली, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, स्टैंड अप इंडिया और तत्काल भुगतान सेवा, डिजिटल आयुष्मान भारत मिशन से भी समाज के करोड़ों लोग लाभांवित हो रहे हैं। डिजिटल पैमेंट के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल है और भारत में अमरीका, यूके और जर्मनी जैसे बड़े देशों को पीछे कर दिया है। ये सब सेवाएं भारत में डिजिटल गवर्नेंस के एक नए युग की प्रतीक हैं।

इतना ही नहीं किसानों के समावेशी विकास में भी डीबीटी की अहम भूमिका है। एक जनवरी 2023 से डिजिटल राशन प्रणाली से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाय) के तहत 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को हर महीने खाद्यान्न निशुल्क प्रदान किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुताबिक 27 फरवरी 2023 तक किसान सम्मान निधि योजना के तहत 13 किस्तों में 11 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में डीबीटी से सीधे करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक हस्तांतरित किए जा चुके हैं।

मौजूदा दौर में श्रमिक दिवस की प्रासंगिकता

योगेश कुमार

उद्योग, व्यापार, भवन निर्माण, पुल, सडक़ों का निर्माण, कृषि इत्यादि समस्त क्रियाकलापों में श्रमिकों के श्रम का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है और वर्तमान मशीनी युग में भी उनकी महत्ता कम नहीं है। सही मायनों में विश्व की उन्नति का दारोमदार इसी वर्ग के मजबूत कंधों पर होता है। किसी भी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति तथा राष्ट्रीय हितों की पूर्ति का प्रमुख भार श्रमिक वर्ग के कंधों पर होता है। समाज के इसी वर्ग के लिए प्रतिवर्ष 1 मई को 'अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस' अथवा 'मजदूर दिवस' मनाया जाता है, जिसे 'मई दिवस' भी कहा जाता है। भारत में श्रमिक दिवस मनाए जाने की शुरुआत किसान मजदूर पार्टी के कामरेड नेता सिंगारावेलू चेट्यार के सुझाव पर 1 मई 1923 को हुई थी। उनका कथन था क्योंकि दुनियाभर के मजदूर इस दिन को मनाते हैं, इसलिए भारत में भी इसे मनाया जाना चाहिए। इस प्रकार भारत में 1 मई 1923 से मई दिवस को राष्ट्रीय अवकाश के रूप मान्यता दी गई। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाए जाने की शुरुआत अमरीका में 8 घंटे से ज्यादा काम न कराने के लिए की गई कुछ मजदूर यूनियनों की हड़ताल के बाद 1 मई 1886 से हुई थी। दरअसल वह ऐसा समय था, जब कार्यस्थल पर मजदूरों को चोट लगना या काम करते समय उनकी मृत्यु हो जाना आम बात थी। ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने, कार्य करने के घंटे कम करने तथा सप्ताह में एक दिन के अवकाश के लिए मजदूर संगठनों द्वारा पुरजोर आवाज उठाई गई। 1 मई 1886 का ही वह दिन था, जब वह हड़ताल हुई थी और शिकागो शहर के हेय मार्केट चौराहे पर उनकी रोज सभाएं होती थी। 4 मई 1886 को जब शिकागो के हेय मार्केट में उस हड़ताल के दौरान पुलिस भीड़ को तितर-बितर करने का प्रयास कर रही थी, उसी दौरान किसी अज्ञात शख्स ने एकाएक भीड़ पर बम फैंक दिया।

उसके बाद पुलिसिया गोलीबारी के कारण कई श्रमिक मारे गए। हालांकि उस समय अमरीकी प्रशासन पर उन घटनाओं का कोई असर नहीं पड़ा लेकिन बाद में श्रमिकों के लिए 8 घंटे कार्य करने का समय निश्चित कर दिया गया। मजदूरों पर गोलीबारी और मौत के दर्दनाक घटनाक्रम को स्मरण करते हुए ही 1 मई 1886 से अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाने लगा। 1889 में पेरिस में अंतरराष्ट्रीय महासभा की द्वितीय बैठक में फ्रांसीसी क्रांति को याद करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया कि इसे 'अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस' के रूप में मनाया जाए। उसी समय से विश्वभर के 80 देशों में 'मई दिवस' को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मान्यता प्रदान की गई। भारत में 'मई दिवस' मनाए जाने की शुरुआत किसान मजदूर पार्टी के कामरेड नेता सिंगारावेलू चेट्यार के सुझाव पर 1 मई 1923 को हुई थी। उनका कथन था कि दुनियाभर के मजदूर इस दिन को मनाते हैं, इसलिए भारत में भी इसे मनाया जाना चाहिए। इस प्रकार भारत में 1 मई 1923 से मई दिवस को राष्ट्रीय अवकाश के रूप मान्यता दी गई। श्रमिक वर्ग ही है, जो अपनी मेहनत के बलबूते पर राष्ट्र के प्रगति चक्र को तेजी से घुमाता है लेकिन कर्म को ही पूजा समझने वाला यह वर्ग श्रम कल्याण सुविधाओं के लिए आज भी तरस रहा है। मई दिवस के अवसर पर देशभर में भले ही मजदूरों के हितों की बड़ी-बड़ी योजनाएं बनती हैं, ढ़ेरों लुभावने वायदे किए जाते हैं, जिन्हें सुनकर एकबारगी तो लगता है कि उनके लिए अब कोई समस्या नहीं बचेगी, किंतु अगले ही दिन मजदूरों को पुनः उसी माहौल से रू-ब-रू होना पड़ता है, फिर वही शोषण, अपमान और जिल्लत भरा जीवन जीने के लिए अभिशप्त होना पड़ता है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर किसके लिए मनाया जाता है 'श्रमिक दिवस'? बहुत से मजदूरों की तो इस दिन भी काम करने के पीछे यही मजबूरी होती है कि यदि वे एक दिन भी काम नहीं करेंगे, तो उनके घरों में चूल्हा कैसे जलेगा? विडंबना है कि देश की स्वाधीनता के साढ़े सात दशक से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी अनेक श्रम कानूनों को अस्तित्व में लाने के बावजूद हम ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर पाए हैं, जो मजदूरों को उनके श्रम का उचित मूल्य दिला सके। भले ही इस संबंध में कई कानून बने हैं, किंतु श्रमिक वर्ग की समस्याएं इसके बावजूद कम नहीं हैं।

हालांकि सच यह भी है कि अधिकांश श्रमिक या तो अपने अधिकारों के प्रति अनभिज्ञ होते हैं या वे अपने अधिकारों के लिए इस कारण आवाज नहीं उठा पाते कि कहीं इससे नाराज होकर उनका मालिक उन्हें काम से न निकाल दे और उनके परिवार के समक्ष भूखे मरने की नौबत आ जाए। जहां तक मजदूरों द्वारा अपने अधिकारों की मांग का सवाल है तो मजदूरों के संगठित क्षेत्र द्वारा ऐसी मांगों पर उन्हें अकसर कारखानों के मालिकों की मनमानी और तालाबंदी का शिकार होना पड़ता है और प्रायः जिम्मेदार अधिकारी भी कारखानों के मालिकों के मनमाने रवैये पर लगाम लगाने की चेष्टा नहीं करते। जहां तक मजदूर संगठनों के नेताओं द्वारा मजदूरों के हित में आवाज उठाने की बात है तो आज के दौर में अधिकांश ट्रेड यूनियनों के नेता भी भ्रष्ट राजनीतिक तंत्र का हिस्सा बने हैं, जो विभिन्न मंचों पर श्रमिकों के हितों के नाम पर शोर तो बहुत मचाते नजर आते हैं लेकिन अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति हेतु कारखानों के मालिकों से सांठगांठ कर अपने ही श्रमिक साथियों के हितों पर कुल्हाड़ी चलाने में संकोच नहीं करते।

वैद्यानिक सूचना

उत्तराखंड प्रहरी के संपादन में हम प्रयासरत है कि हमारी ओर से खबर में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि न हो। हमारी कोशिश है कि अखबार में छपी किसी खबर, रिपोर्ट, फीचर या लेख से व्यक्ति विशेष, संगठन या समुदाय की भावना को ठोस न पहुंचे। **उत्तराखंड प्रहरी** में प्रकाशित लेख, विश्लेषण और साभार, ली गई सामग्री के विचार संबंधित लेखकों और रचनाकारों के निजी विचार हैं, न कि अखबार के। अतः सभी पाठकों से आग्रह है कि वे किसी सूचना, समाचार, विज्ञापनों आदि के आधार पर कोई फैसला करने से पहले तथ्यों की स्वयं पुष्टि कर लें। उसके लिए किसी भी प्रकार से लेखक, संपादक, प्रकाशक, प्रिंटर या विक्रेता को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। तथा किसी भी कारोबारी और निज निर्णय के लिए **उत्तराखंड प्रहरी** जिम्मेवार नहीं होगा।

प्रदेशभर में सुना गया प्रधानमंत्री के 'मन की बात' कार्यक्रम का 100 वां संस्करण

उत्तराखंड प्रहरी ब्यूरो

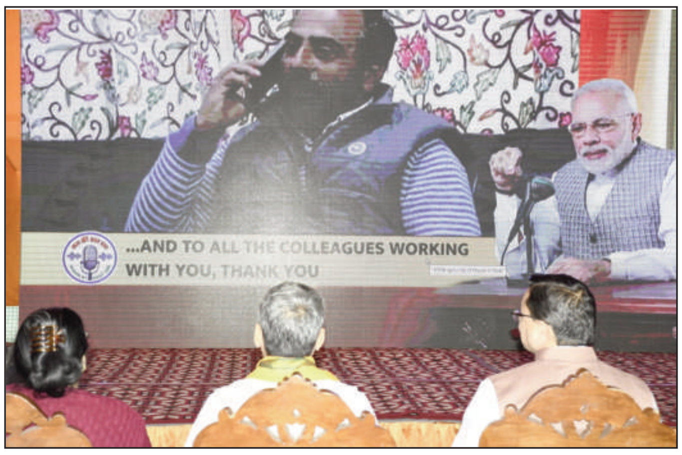

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल के डीएसए मैदान, मल्लीताल से सुनी पीएम के मन की बात

मुख्यमंत्री ने पीएम के वचनों को बताया प्रेरणादायी, कहा मन की बात से जुड़ा है जन-जन

नैनिताल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को डीएसए मैदान, मल्लीताल, नैनीताल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100 वां संस्करण सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि 03 अक्टूबर, 2014 से अनवरत रूप से प्रसारित हो रहे मन की बात कार्यक्रम का 100 वें संस्करण ने ऐतिहासिक मिसाल कायम की है।

मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री के वचनों को प्रेरणादायी बताते हुए कहा कि 'मन की बात' कार्यक्रम ने आज तमाम भारतीयों के जीवन को बदलने का काम किया है। समाज के अंतिम छोर पर काम कर रहे व्यक्ति के समाज के लिए अथक प्रयासों का जिक्र इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री करते हैं जो समाज के लिए प्रेरणादायी है। उन तमाम लोगों का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने 'मन की बात' में किया है जो चुपचाप समाज सेवा में जुटे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम की 'मन की बात' से आज जन-जन जुड़ा हुआ है। सीएम ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम ने देशवासियों को जोड़कर एक नई सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने का कार्य है। मन की बात कार्यक्रम ने सरकारी योजनाओं में सामूहिक जनसहभागिता को जोड़कर सफल बनाया है। वहीं संघर्षरत युवाओं के अधूरे सपने को साकार करने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में मानसखंड मंदिर माला मिशन से पर्यटकों की संख्या मे इजाफा होगा व पहाड़ की आर्थिकी सशक्त होगी। इसके साथ ही *वोकल फोर लोकल* को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की स्वयं सहायता समूह को सशक्त किया गया है व उनके उत्पादों की बेहतर ब्रांडिंग की जा रही है। 'लोकल फोर ग्लोबल' के लिए स्थानीय उत्पादों में मूल्य सम्वर्द्धन किया जा रहा है। मूल्य संवर्धन से काश्तकारों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रेरक शब्दों का अनुसरण कर हम उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए संकल्पित हैं। उत्तराखंड में भी पीएम की 'मन की बात' कार्यक्रम को सुनने के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। स्कूल, कॉलेज इत्यादि में भारी संख्या में छात्रों के साथ आम लोगों ने पीएम के मन की बात को सुना। इस अवसर पर विधायक सरिता आर्य, जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल, एस एस पी पंकज पांडेय, जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट, राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी महेंद्र पांडेय, सांसद प्रतिनिधि गोपाल रावत, डॉ अनिल कपूर डब्बू, सीडीओ संदीप तिवारी, अपर जिलाधिकारी अशोक जोशी, उपजिलाधिकारी राहुल शाह, परितोष वर्मा, आंनद बिष्ट, दया किशन पोखरिया, मनोज जोशी, सीएमओ डॉ भागीरथी जोशी सहित स्कूली बच्चे व आमजनता उपस्थित थी।

टीम आस्था ने गंगा घाटों पर चलाया स्वच्छता और जागरूक अभियान

हरिद्वार। देवभूमि हरिद्वार में टीम आस्था के संस्थापक अमित कुमार मुल्तानीया के नेतृत्व में देवभूमि का सबसे बड़ा स्वच्छता व जागरूकता अभियान रविवार को चौधरी चरण सिंह घाट सिंहद्वार पर पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं एवं गंगा भक्तों के सहयोग से चलाया गया जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता गंगा भक्त अभियान का हिस्सा बने। सोशल मीडिया प्रभारी अंजली ने कहा कि अभियान के माध्यम से मां गंगा की आस्था व पवित्रता को बनाए रखने के संदेश सभी गंगा भक्त देशभर में देते हैं आने वाली पीढ़ी को नया और बेहतर कल मिले ऐसा प्रयास हम सबको। मिलकर करना होगा।

गीता ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी से पौधारोपण करने की अपील की। गंगा भक्त अनुज कश्यप ने सभी युवा वर्ग से अभियान के माध्यम से निवेदन किया कि अभियान में सेवा देकर प्रत्येक सप्ताह हम देवभूमि हरिद्वार को सबसे सुंदर बना सकें ऐसा प्रयास सबको करना होगा।

आकाश बायजूस के चार छात्रों ने जेईई मेन में पाई सफलता

छात्रों ने मेहनत कर हासिल की अनुकरणीय उपलब्धि: अभिषेक महेश्वरी

उत्तराखंड प्रहरी ब्यूरो

हरिद्वार। हरिद्वार के आकाश बायजूस के 4 छात्रों ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) मेन 2023 में 99 पर्सेंटाइल और उससे अधिक अंक हासिल कर अपने माता-पिता औरसंस्थान के पूरे स्टाफ को बहुत खुश किया। परिणाम कल राष्ट्रीयपरीक्षण द्वारा घोषित किए गए थे। उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वालों में ईशान जाजोदिया हैं जिन्होंने 99.92, रवित चतरथ ने 99.77, नमन सिंघल ने 99.46, समृद्धि मारवाहा ने 99.04 और इशान ढींगरा ने 98.85 अंकहासिल किए हैं। दुनिया की सबसे कठिन प्रवेश परीक्षा मानी जाने वाली आईआईटी जेईई को क्रैक करने के लिए छात्र आकाश बायजू के क्लासरूम प्रोग्राममें शामिल हुए। उन्होंने जेईई में टॉप पर्सेंटाइल की एलीट लिस्ट मेंअपने प्रवेश का श्रेय कॉन्सेप्ट को समझने और सीखने केकार्यक्रम का सख्ती से पालन किया। हम आभारी हैं किआकाश बायजूस ने दोनों के साथ हमारी मदद की है। अन्यथा संस्थान से सामग्री और कोचिंग के लिए, हम कम समय मेंविभिन्न विषयों में कई अवधारणाओं को नहीं समझ पाते। छात्रों को बधाई देते हुए, अभिषेक माहेश्वरी, मुख्य कार्यकारीअधिकारी, आकाश बायजूस ने कहा, "हम सभी छात्रों को उनकेअनुकरणीय उपलब्धि के लिए बधाई देते हैं। शीर्ष पर्सेंटाइलस्कोरर के रूप में उनकी उपलब्धि उनकी कड़ी मेहनत और समर्पणके बारे में बताती है। हम उनके भविष्य के प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं देते हैं।"

जेईई (मेन) छात्रों को अपने स्कोर में सुधार करने के लिए कईअवसर देने के लिए दो सत्रों में आयोजित किया जाता है। जबकिजेईई एडवांस केवल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में प्रवेश के लिए है, जेईई मेन भारत में कई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकीसंस्थान (एनआईटी) और अन्य केंद्र-सहायता प्राप्त इंजीनियरिंगकॉलेजों में प्रवेश के लिए है। जेईई एडवांस में बैठने के लिए छात्रोंको जेईई मेन में शामिल होना पड़ता है

आकाश बायजू हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों केलिए कई कोर्स फॉर्मेट में आईआईटी-जेईई कोचिंग प्रदान करताहै। हाल के दिनों में, आकाश ने कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षणविकसित करने पर अपना ध्यान बढ़ाया है। इसका आईट्यूटर रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर प्रदान करता है। मॉक टेस्ट वास्तविकपरीक्षा परिदृश्य का अनुकरण करते हैं, इस प्रकार छात्रों कोपरीक्षा का सामना करने के लिए आवश्यक परिचितता और आत्मविश्वास प्रदान करते हैं।

गंगा सेवक दल ने गंगा घाटों पर चलाया सफाई अभियान

उत्तराखड प्रहरा ब्यूरा

हरिद्वार। रविवार को श्री गंगा सभा के गंगा सेवक दल के तत्वाधान में डॉ. हरिराम आर्य इंटर कॉलेज के पूर्व छात्रों, पार्षद अनुज सिंह एवं बीपीसीएल ने कनखल के सती घाट पर बृहत गंगा घाट स्वच्छता अभियान चलाया गया।

गंगा सेवक दल के सचिव उज्ज्वल पंडित का कहना है कि पिछले लंबे समय से श्री गंगा सभा को सती घाट पर बड़ी मात्रा में रेलिंग में फंसी कांवड़, कपड़ा एवं अन्य सामानों की वीडियोज-फोटोज मिल रहे थे। जिसके बाद हमने संकल्प लिया और अपने साप्ताहिक अभियान के तहत आज यह अभियान चलाने के बाद घाट की तस्वीर पूरी तरह बदल दी गई। नगर निगम पार्षद अनुज सिंह व डॉ. हरिराम आर्य इंटर कॉलेज के पूर्व छात्र संगठन से नीरज गुप्ता ने कहा कि दृढ़ विश्वास के साथ किया गया प्रत्येक असंभव कार्य को भी संभव किया जा सकता हैं। उन्होंने कहा की लोग ऐसे फोटोज को सोशल मीडिया पर अपलोड कर अपनी फॉलोइंग तो बढ़ाते है लेकिन धरातल पर इन कार्यों करने से हिचकते हैं। आज श्री गंगा सभा के गंगा सेवक दल के तत्वाधान में डॉ. हरिराम आर्य इंटर कॉलेज के पूर्व छात्र, पार्षद अनुज सिंह एवं बीपीसीएल ने कनखल के सती घाट पर बृहत गंगा घाट स्वच्छता अभियान चलाया गया। बीपीसीएल के वरिष्ठ अधिकारी अभिनव मिश्र वा मुनीश शर्मा ने कहा कि गंगा सभा का यह अभियान वाकई प्रशंसनीय है जिनकी प्रेरणा के कारण आज हम इस अभियान से जुड़कर अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं हर भारतवासी को गंगाजी को स्वच्छ रखने के अभियान से जुड़ना चाहिए। इस अवसर पर शिवांकर चक्रपाणि, दीपांकर चक्रपाणि, टिमटिम सिखौला, वैभव भगत, तनिष्क शर्मा, एकलव्य पंडित, गोविंद झा तथा डॉ. हरिराम आर्य इंटर कॉलेज के पूर्व छात्र नीरज गुप्ता, नंदकिशोर काला, प्रदीप चौहान, जय भगवान गुप्ता, सत्य प्रकाश, सत्यदेव राठी एवं सुधीर शर्मा आदि मौजूद रहे।

चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग

उत्तराखंड प्रहरी ब्यूरो

हरिद्वार। विष्णु लोक समिति एवं दुर्गा विहार के सभी लोगो ने ज्वालापुर थाना प्रभारी कुंदन सिंह राणा को ज्ञापन सौंपा। कॉलोनियों में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग उठाई।

विष्णु लोक लक्ष्मी विहार दुर्गा विहार श्रीराम एनक्लेव क्षेत्र में दिन रात किसी भी समय चोर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं जिससे कॉलोनी मैं दहशत का माहौल बना हुआ है। अध्यक्ष एवं शिवसेना के जिला प्रभारी विशाल शर्मा ने थाना प्रभारी से क्षेत्र में चेतक की गस्त बढ़ाने के लिए कहा एवं पुलिस बीट जगह जगह लगाने के लिए मांग की जिससे चोर चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम ना दे सके और कॉलोनी वासी चैन की नींद सो सके। ज्ञापन देने वालों में आर्मी रिटायर कैप्टन विपिन जोशी, उत्तराखंड आंदोलनकारी राजेंद्र कुमार ,रामधन, सुधीर मिश्रा, नितिन शर्मा, सूर्यांश कुमार, देवेंद्र सिंह बिष्ट, कुंदन सिंह, रतुला, गुड्डू कुमार आदि उपस्थित रहे।

सशक्त उत्तराखण्ड बनाना हमारी प्रतिबद्धताः मुख्यमंत्री

- प्रदेश में समावेशी विकास एवं सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के लिये बनाया जा रहा है अनुकूल माहौल
- प्रदेश के समग्र विकास के लिये आगामी 10 सालों का रोड मैप किया जा रहा है तैयार
- समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट जून तक हो जायेगा तैयार
- प्रदेश में सरकारी भूमि पर होने वाला अतिक्रमण रोका जायेगा सख्ती से
- चारधाम यात्रा के लिये देवभूमि के द्वारा सभी के लिये है खुले

उत्तराखंड प्रहरी ब्यूरो

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मालसी स्थित होटल में ''न्यूज 18 इण्डिया ओपन माइक उत्तराखण्ड'' कार्यक्रम में राज्य से संबंधित विभिन्न विषयों पर बेबाकी से अपने विचार रखे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके कार्यव्यवहार में सौम्यता जरूर है लेकिन राज्य के व्यापक हित में कठोर निर्णय लेने में भी वे पीछे नही हटते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की देवतुल्य जनता ने राज्य में एक ही दल की सरकार को दुबारा न चुनने के मिथक को तोडा है। प्रदेश हित में हमने जो भी वायदे किये हैं उन्हे पूरा करने तथा 2025 तक उत्तराखण्ड को देश के अग्रणी राज्यों में सम्मिलित करने के लिये वे प्राण प्रण से जुटे हैं। प्रदेश के समग्र विकास में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ केन्द्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सशक्त उत्तराखण्ड बनाने की हमारी प्रतिबद्धता है। इसके लिये प्रदेश में समावेशाी विकास एवं सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के लिये अनुकूल माहौल तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिये आगामी 10 सालों का रोड मैप तैयार करने के निर्देश सभी विभागों को दिये गये है। कृषि, बागवानी आदि के साथ प्राथमिक सैक्टरों को भी इसमें सम्मिलित किया जा रहा है। यही नही तमाम अनछुए क्षेत्रों को बढावा देने का भी कार्य हो रहा है। एक लाख पोली हाउसों के निर्माण से 05 लाख लोगों को रोजगार देने की योजना पर भी कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों से बेरोजगारी दूर नही की जा सकती इसके लिये स्वरोजगार की योजनाओं को बढावा दिया जा रहा है। हमारे युवा नौकरी मांगने वाले नहीं नौकरी देने वाले बने, इस दिशा में प्रभावी पहल की जा रही है। उन्होंने कहा कि जोशीमठ भू-धसाव से हुए प्रभावितों के साथ राज्य सरकार पूरी तरह सहयोगी के रूप में खडी है। इस कठिन दौर में राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा पूरी मदद दी जा रही है। जोशीमठ को बचाना हमारी प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधामों में हो रही वर्षा एवं बर्फबारी के बावजूद यात्रा अपने चरम पर है, लोगों की सुरक्षित एवं सुगम यात्रा के लिये कारगर व्यवस्था की जा रही है। जोशीमठ का कुछ क्षेत्र ही भू-धसाव से प्रभावित है। जोशीमठ में यात्रियों के लिये आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा के लिये देवभूमि के द्वार सभी के लिये खुले है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड धर्म, संस्कृति एवं आध्यात्म के साथ गंगा एवं यमुना का प्रदेश है। राज्य की सीमायें दो देशों से जुडी है। सैन्य बाहुल्य इस देवभूमि में रहने वाले सभी जाति, पंथ, संप्रदाय के लोगों के लिये बिना किसी तुष्टिकरण के सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास की भावना के अनुरूप समान नागरिक संहिता बनाये जाने पर तेजी से कार्य हो रहा है। जून तक इसका ड्राफ्ट तैयार हो जायेगा। उत्तराखण्ड देश में इस कानून को लागू करने वाला पहला प्रदेश होगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के अन्य राज्य भी इस दिशा में आगे आयेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नही होने दिया जायेगा, साथ ही ऐसे अतिक्रमणों को स्वयं हटाने के लिये सभी संबंधित से अपेक्षा भी की गयी है। तय समय सीमा में अतिक्रमण न हटाये जाने पर उन्हें हटाये जाने की कार्यवाही के भी सख्त निर्देश अधिकारियों को दिये गये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखण्ड के प्रति विशेष लगाव राज्य के विकास से जुडी योजनाओं में साफ झलकता है। शीघ्र ही ऋषिकेश, कर्णप्रयाग रेललाइन का सपना साकार होने वाला है।

सावधान : केदारनाथ मन्दिर में चढ़ावा चढ़ाने के लिए लगाया पेटीएम क्यू आर कोड ?

चोरों ने निकाला ठगी का नया तरीका

उत्तराखंड प्रहरी ब्यूरो

हरिद्वार। केदारनाथ मंदिर में भक्तों के लिए पेटीएम क्यूआर कोड स्कैन की जिस सुविधा का चर्चा हर ओर हो रहा है। उस डिजिटल डोनेशन का बड़ा खेल सामने आया है। बताया जा रहा है कि श्री केदारनाथ व श्री बदरीनाथ में मंदिरों में विभिन्न स्थानों पर डिजिटल दान के लिए लगे क्यूआर कोड श्री बदरीनाथ – केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) की ओर से नहीं लगाए गए है। जिससे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये डोनेशन जा कहां रहा है और इसे किसने लगाया है। मामले में समीति ने रविवार को पुलिस को तहरीर देकर इसकी जांच की मांग की है।

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार केदारनाथ मंदिर चार धाम यात्रा का सबसे दूरस्थ तीर्थ स्थान है और मंगलवार को इसके कपाट भक्तों के लिए फिर से खोल दिए गए थे। धाम के जब कपाट खुले तो मंदिर परिसर के बाहर एक बाहर QR CODE लगे थे जिसमे डिजिटली पैसे दान करने की बात कही गई। कहा गया कि मंदिर में आने वाले भक्त पेटीएम क्यूआर कोड को आसानी से स्कैन कर सकते हैं और पेटीएम वॉलेट, पेटीएम यूपीआई लाइट, पेटीएम पोस्टपेड और अन्य भुगतान विधियों के अलावा पेटीएम यूपीआई के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। लेकिन अब मामले में नया मोड़ आ गया है।

बताया जा रहा है कि बीकेटीसी द्वारा वर्तमान में अपने कामकाज में पेटीएम का प्रयोग नहीं किया जाता है। पेटीएम QR CODE के बारे में समीति के अधिकारियों के संज्ञान में आने पर उसी दिन बोर्ड उतार दिए गए थे। बीकेटीसी अधिकारियों ने पहले अपने स्तर से इस मामले की छानबीन की। जिसके बाद आज (रविवार) केदारनाथ के मंदिर अधिकारी द्वारा केदारनाथ पुलिस चौकी और बदरीनाथ में प्रभारी अधिकारी की ओर से मामले की कोतवाली में तहरीर दी है। साथ ही मामले की जांच करने की अपील भी की गई है।

खिलाड़ियों के समर्थन में उतरी किसान मजदूर उत्थान यूनियन

शीघ्र महिला खिलाड़ियों को सुरक्षा और न्याय दिया जाएः विनोद कश्यप

पहलवानों के आंदोलन को वर्ग विशेष से जोड़ भाजपा ने दिखाई ओछी मानसिकता: इरशाद अली

उत्तराखंड प्रहरी ब्यूरो

हरिद्वार। दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने पर बैठी महिला खिलाड़ियों को लेकर हर तरफ रोष बढ़ता जा रहा है। खिलाड़ियों के समर्थन में हर तरफ से आवाज बुलंद होने लगी है। इसी कड़ी में भारतीय किसान मजदूर उत्थान यूनियन ने खिलाड़ियों को अपना समर्थन देते हुए उन्हें सुरक्षा और न्याय देने की मांग की है। ऐसा नहीं होने पर देशभर में उग्र आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। भारतीय किसान मजदूर उत्थान यूनियन के राट्रीय अध्यक्ष ने अपने पदाधिकारियों साथ दिल्ली में पहुंचकर महिला खिलाड़ियों को अपना समर्थन दिया है। जमालपुर जियापोता रोड स्थित राष्ट्रीय कार्यालय पर भारतीय किसान मजदूर उत्थान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव इरशाद अली के नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव इरशाद अली ने कहा कि किसान वर्ग के बेटों और बेटियों ने देश के लिए सर्वाधिक मेडल जीतकर नाम रोशन किया। मगर जब अब पहलवान आंदोलन कर रहे हैं तो उसे वर्ग विशेष से जोड़कर भाजपा ने अपनी ओछी मानसिकता का परिचय दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों के बच्चों की सफलता कुछ लोगों को पच नहीं रही है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का गौरव बढ़ाने वाली महिला खिलाड़ी की बात नहीं सुनी जा रही है। देश में आम महिलाओं की क्या दुर्गति होगी। इसका अनुमान इस बात से आसानी से लगाया जा सकता है।

इरशाद अली ने कहा कि किसान मजदूर यूनियन देश का गौरव बढ़ा रही महिला खिलाड़ियों का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने केंद्र सरकार को चेतावनी भरे लहजे में अनुरोध करते हुए कहा कि जल्द से जल्द महिला खिलाड़ियों को सुरक्षा एवं न्याय दिलाया जाए। अन्यथा भारतीय किसान मजदूर यूनियन राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने बताया कि किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी महिला पहलवान खिलाड़ियों के समर्थन बैठे हुए हैं। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष विनोद कश्यप कहा कि एक तरफ भाजपा सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है और दूसरी तरफ उनकी ही सरकार में बेटियों का उत्पीड़न हो रहा है।

देश का गौरव महिला खिलाड़ी दिल्ली में धरने पर बैठी हुई है। लेकिन उनकी सुनवाई करने के लिए सरकार का कोई नुमाइंदा तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस में भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की है। एक नाबालिक ने भी शिकायत दर्ज कराई है। पोक्सो एक्ट में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है लेकिन सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो भारतीय किसान मजदूर उत्थान यूनियन खिलाड़ियों के साथ दिल्ली में चल रहे धरने पर बैठेंगे। बैठक में प्रदेश संयोजक राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी, राष्ट्रीय सलाहकार यशपाल चौधरी, प्रदेश सचिव मोहम्मद अकील, अग्रज मिश्रा, पंकज कश्यप, सावेद मलिक, प्रशांत चौधरी, आलम, विकास, गुड्डू मिश्रा, दीपक सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

श्रमिकों, छोटे कारोबारियों के लिए शुरू की गई पेंशन योजनाएं पड़ीं सुस्त, पंजीकृत लोगों की संख्या घटी

नई दिल्ली। सरकार की श्रमिकों, छोटे व्यापारियों और किसानों के लिए जोर-शोर से शुरू की गई महत्वाकांक्षी पेंशन योजनाएं अब सुस्त पड़ती जा रही हैं। इसमें न केवल पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या कम हुई है बल्कि बजट आवंटन भी या तो स्थिर बना हुआ है अथवा उसमें गिरावट आई है। पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने बजट पर लिखी अपनी नई पुस्तक में यह दावा किया है।

सरकार ने 2019-20 के अंतरिम बजट में अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले 42 करोड़ लोगों के योगदान की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की थी। श्रमिकों के लिए पेंशन कार्यक्रम... श्रम योगी मानधन योजना सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं में शामिल है। वित्त मंत्री ने उस समय अपने बजट भाषण में कहा था, हमारी सरकार 15,000 रुपए तक मासिक आय वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बड़ी पेंशन योजना शुरू करने का प्रस्ताव करती है। यह पेंशन योजना उन्हें छोटी राशि का योगदान कर 60 वर्ष की आयु से 3,000 रुपए मासिक पेंशन की गारंटी देगी...।

बजट प्रस्ताव के अनुसार, इस पेंशन योजना के तहत 29 साल के कामगार को 60 साल की उम्र तक 100 रुपए प्रतिमाह का योगदान देना होगा। वहीं 18 वर्ष के कामगार को योजना से जुड़ने के लिए 55 रुपए प्रतिमाह का योगदान देना होगा। सरकार उतनी ही राशि कर्मचारी के पेंशन खाते में हर महीने जमा करेगी। गर्ग ने एक्सप्लैनेशन एंड कॉमेन्टरी ऑन बजट 2023-24 शीर्षक से लिखी पुस्तक में दावा किया है, श्रम योगी मानधन योजना (2019-20) के पहले साल में अच्छी संख्या में श्रमिक और कामगार आकर्षित हुए। योजना के तहत 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार 43,64,744 श्रमिक पंजीकृत हुए। लेकिन बाद में योजना को लेकर असंगठित क्षेत्र के कामगारों की रुचि कम होती गई। वित्त वर्ष 2020-21 में केवल 1,30,213 कामगार पंजीकृत हुए और इससे कुल पंजीकृत श्रमिकों और कामगारों की संख्या बढ़कर 44,94,864 हो गई। उन्होंने लिखा है, वित्त वर्ष 2021-22 में 1,61,837 कामगार योजना में पंजीकृत हुए। इससे पंजीकृत कामगारों की संख्या 31 मार्च, 2022 तक बढ़कर 46,56,701 पहुंच गई। ऐसा लगता है कि उसके बाद जनवरी, 2023 से कामगारों ने पंजीकरण रद्द कराना शुरू कर दिया।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के डैशबोर्ड के अनुसार, जनवरी, 2023 को 56,27,235 पहुंचने के बाद पंजीकृत कामगारों की संख्या में कमी आई और यह मार्च, 2023 में 44,00,535 पर आ गई। वित्त वर्ष 2019-20 के अंतरिम बजट में पांच साल में इस पेंशन योजना से असंगठित क्षेत्र के करीब 10 करोड़ श्रमिकों के जुड़ने की उम्मीद जताई गई थी। उसके मुकाबले अबतक पंजीकृत श्रमिकों और कामगारों की संख्या काफी कम है।

इसके अलावा सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में 2019-20 के पूर्ण बजट में 1.5 करोड़ सालाना से कम कारोबार वाले तीन करोड़ खुदरा कारोबारियों, छोटे दुकानदारों और अपना कारोबार करने वाले व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना...प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना शुरू की। साथ ही छोटे और सीमांत किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना शुरू की गई।

श्रम मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार, कर्मयोगी मानधन योजना में 30 अप्रैल, 2023 की स्थिति के अनुसार 52,472 छोटे कारोबारी और दुकानदार जुड़े।

रिलायंस-बीपी, नायरा ने बाजार मूल्य पर पेट्रोल, डीजल बेचना शुरू किया

नई दिल्ली। निजी क्षेत्र की ईंधन खुदरा विक्रेता रिलायंस-बीपी और रूस की रोसनेफ्ट समर्थित नायरा एनर्जी ने एक साल से अधिक समय में पहली बार बाजार कीमतों पर पेट्रोल और डीजल की बिक्री शुरू की है।

सूत्रों ने बताया कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बाद यह फैसला किया गया।

रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड (आरबीएमएल), नायरा एनर्जी और शेल ने पेट्रोल और डीजल को भारी घाटे में बेचा, क्योंकि उसे सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों का मुकाबला करना था, जो पहले ही कम दरों पर बिक्री कर रही थीं।

आरबीएमएल, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ब्रिटेन स्थित बीपी का संयुक्त उद्यम है। इन कंपनियों ने सरकारी पेट्रोलियम विपणन कंपनियों-इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) की तुलना में थोड़ी अधिक कीमत पर ईंधन बेचा।

मामले की जानकारी रखने वाले तीन सूत्रों ने कहा कि पिछले छह सप्ताह में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट ने खुदरा दरों को लागत के बराबर लाने में मदद की है।

भारत के 86,855 पेट्रोल पंप में सात प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व रखने वाली नायरा ने मार्च में बाजार दरों पर पेट्रोल और डीजल को बेचना शुरू किया, जबकि आरबीएमएल के 1,555 पेट्रोल पंप पर इस महीने से डीजल को बाजार मूल्य पर बेचा जा रहा है।

उन्होंने कहा कि कच्चे तेल की कीमतें इस सप्ताह उच्च स्तर से गिरकर 78 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर आ गई हैं।

इस गिरावट के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि सरकारी पेट्रोलियम कंपनियां भी कीमतों में कमी कर सकती हैं।

तेल, जस्ता उत्पादन बढ़ाने की योजना पर ध्यान दे रहे हैं वेदांता के सीईओ अनिल अग्रवाल

नई दिल्ली। खनन क्षेत्र के दिग्गज उद्यमी अनिल अग्रवाल तेल और गैस व जस्ता और एल्युमिनियम जैसी धातुओं का उत्पादन बढ़ाने और सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में उतरने की आक्रामक योजना पर ध्यान दे रहे हैं। वह कंपनी पर कर्ज स्तर को लेकर बिल्कुल चिंतित नहीं हैं। पटना में पले-बढ़े अग्रवाल ने 15 वर्ष की आयु में स्कूल छोड़ दिया था। उन्होंने 1976 में मुंबई में कबाड़ कारोबारी के तौर पर अपना व्यापार शुरू किया। अब वह खनन और धातु कारोबार का परिचालन करते हैं, जो ब्रिटेन, भारत, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया तक फैला है।

अग्रवाल ने पीटीआई-भाषा से बातचीत में कहा कि खनन की मदद से भारत समृद्ध हो सकता है क्योंकि जमीन के अंदर दबे प्राकृतिक संसाधनों से न सिर्फ आयात पर निर्भरता कम होगी बल्कि रोजगार भी पैदा होगा। उन्होंने वेदांता की स्थापना की थी और अब वह इसके चेयरमैन हैं। कंपनी की तेल और गैस से लेकर जस्ता और एल्युमिनियम उत्पादन बढ़ाने की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। उन्होंने कहा, हम दो वर्ष में तीन लाख बैरल तेल (और तेल बराबर गैस) और चार-पांच वर्ष में पांच लाख बैरल का उत्पादन करेंगे।

सड़क परिवहन, राजमार्ग क्षेत्र की सबसे ज्यादा 402 परियोजनाएं अपने समय से पीछे : रिपोर्ट

नई दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग क्षेत्र में सबसे अधिक 402 परियोजनाएं लंबित हैं। इसके बाद रेलवे की 115 और पेट्रोलियम क्षेत्र की 86 परियोजनाएं देरी से चल रही हैं। सरकार की एक रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है। अवसंरचना क्षेत्र की परियोजनाओं पर मार्च, 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, सड़क परिवहन और राजमार्ग क्षेत्र में 749 में से 402 परियोजनाओं में देरी हो रही है। रेलवे की 173 में से 115 परियोजनाएं अपने समय से पीछे चल रही हैं। वहीं पेट्रोलियम क्षेत्र की 145 में से 86 परियोजनाएं अपने निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं।

अवसंरचना एवं परियोजना निगरानी प्रभाग (आईपीएमडी) 150 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं की निगरानी करता है। आईपीएमडी, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

रिपोर्ट से पता चलता है कि मुनीराबाद-महबूबनगर रेल परियोजना सबसे अधिक देरी वाली परियोजना हैं। यह अपने निर्धारित समय से 276 महीने पीछे है। दूसरी सबसे देरी वाली परियोजना उधमपुर-श्रीनगर-बारापूला रेल परियोजना है। इसमें 247 माह का विलंब है। इसके अलावा बेलापुर-सीवुड शहरी विद्युतीकरण दोहरी लाइन परियोजना अपने निर्धारित समय से 228 महीने पीछे है। मार्च, 2023 की रिपोर्ट में 150 करोड़ रुपए या इससे अधिक की लागत वाली केंद्रीय क्षेत्र की 1,449 परियोजनाओं का ब्योरा है। रिपोर्ट के अनुसार, 821 परियोजनाएं अपने मूल समय से पीछे हैं। वहीं 354 परियोजनाएं ऐसी हैं जिनकी लागत बढ़ चुकी है। 247 परियोजनाएं देरी से भी चल रही हैं और इनकी लागत भी बढ़ी है।

कुल 821 परियोजनाएं अपनी मूल निर्धारित समयसीमा से पीछे हैं और 165 परियोजनाएं ऐसी हैं जिनमें पिछले माह की तुलना में विलंब और बढ़ा है। इन 165 परियोजनाओं में से 52 बड़ी यानी 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग क्षेत्र के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि 749 परियोजनाओं के क्रियान्वयन की मूल लागत 4,32,893.85 करोड़ रुपए थी, जिसके अब बढ़कर 4,51,168.46 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इस तरह इन परियोजनाओं की लागत 4.2 प्रतिशत बढ़ी है। मार्च, 2023 तक इन परियोजनाओं पर 2,31,620.94 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जो मूल लागत का 51.3 प्रतिशत है।

इसी तरह रेलवे क्षेत्र में 173 परियोजनाओं के क्रियान्वयन की मूल लागत 3,72,761.45 करोड़ रुपए थी, जिसे बाद में संशोधित कर 6,27,160.59 करोड़ रुपए कर दिया गया। इस तरह इनकी लागत में 68.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इन परियोजनाओं पर मार्च, 2023 तक 3,84,947.64 करोड़ रुपए या परियोजनाओं की अनुमानित लागत का 61.4 प्रतिशत खर्च किया जा चुका है। पेट्रोलियम क्षेत्र की 145 परियोजनाओं के क्रियान्वयन की मूल लागत 3,63,608.84 करोड़ रुपए थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 3,84,082.25 करोड़ रुपए कर दिया गया। इन परियोजनाओं की लागत में 5.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इन परियोजनाओं पर मार्च, 2023 तक 1,52,566.01 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं।

रोमांचक मैच में गिन्नी फिलामेंट की टीम ने एएलएफ को 2 रन से हराया

उत्तराखंड प्रहरी ब्यूरो

सिडकुल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के तत्वाधान में क्रिकेट लीग का तीसरा आयोजन

हरिद्वार। सिडकुल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के तत्वाधान में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट में गिन्नी फिलामेंट की टीम ने 2 रनों के अंतर से रोमांचक जीत दर्ज की। उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए मैच के अंतिम ओवर में एएलएफ के कप्तान को आउट कर जीत हासिल की।

गौरतलब है कि सिडकुल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित क्रिकेट लीग के रोमांचक मैच खेले जा रहे हैं। इस टुर्नामेंट में सिडकुल इंडस्ट्री की 16 टीमें हिंदुस्तान लीवर, सायनोकेम गोदरेज, महिंद्रा एंड महिंद्रा, गिन्नी फिलामेंट्स, हैवेल्स , c&s , टीसीपीएल , लोटस ,एएलएफ,विप्रो,किर्बी इंडो-एशियन, हैवेल्स, विजय इलेक्ट्रिकल्स, होलिनिक्स भाग ले रही हैं। इस टुर्नामेंट का एक बहुत ही रोमांचक मैच में गिन्नी फिलामेंट्स के साथ ए एलएफ टीम का मैच हुआ। जिसमें से गिन्नी फिलामेंट्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और गिन्नी फिलामेंट की पूरी टीम 15 ओवर 4 गेंद में 121 रन बनाकर के ऑल आउट हो गई। सबसे ज्यादा रन विकास सैनी ने बनाया। ए एल एफ को जीत के लिए 20 ओवर में 122 रन का लक्ष्य मिला। जिसमें से गिन्नी ने अपनी कसी हुई गेंदबाजी और फील्डिंग के बदौलत एल्फ के बल्लेबाजों को पवेलियन भेजते रहे। अंत का अंतिम ओवर कप्तान मनीष नौटियाल ने अपने हाथों में लिया जिसमें से 2 रन एलएफ को जीत के लिए चाहिए था। यह मैच काफी उतार-चढ़ाव वाला रहा। कौन सी टीम जीतेगी। इसका अंदाजा कोई लगा नहीं पा रहा था।

अंतिम ओवर जब कप्तान मनीष नौटियाल ने अपने हाथों में लिया तो किसी को यह विश्वास नहीं था कि वह कप्तानी पारी में विकेट लेकर के गिन्नी फिलामेंट को जीत दिला देंगे वही हुआ कप्तान ने टीम मैनेजमेंट पर अपना भरोसा कायम रखा और 16वें ओवर में उन्होंने विकेट लेकर के गिन्नी फिलामेंट को लीग मैच में पहला मैच जिताने में कामयाब रहे। गिन्नी फिलामेंट्स की टीम 2 रन से विजई घोषित हुई। मैच समाप्ति के अंत में सिडकुल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने ए एल एफ की टीम को पुरस्कार दिया एवं गिन्नी फिलामेंट्स फैक्ट्री में अपनी प्रतिद्वंदी टीम एल्फ को सभी को एक एक गिफ्ट देकर के सम्मानित किया और दोनों टीमों ने खेल भावना के साथ खेल खेला इसकी प्रशंसा की इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की तरफ से सुदेश श्रीवास्तव सक्षम पाठक कुल तेज सिंह एवं बी के त्रिपाठी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। गिन्नी फिलामेंट्स अपनी टीम को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदीप पात्रा, मधुकर शर्मा, मुकेश सक्सेना, परविंदर त्यागी, पूनम सारस्वत, प्रियंका, अनिकेत सहित कई लोग उपस्थित थे।

अभिषेक के हरफनमौला खेल से सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया

नई दिल्ली। अभिषेक शर्मा के हरफनमौला खेल और आखिरी ओवरों में हेनरिच क्लासेन की आक्रामक बल्लेबाजी से सनराइजर्स हैदराबाद ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) टी20 मैच में शनिवार को यहां दिल्ली कैपिटल्स को नौ रन से शिकस्त दी।

सलामी बल्लेबाज अभिषेक की 36 गेंद में 67 रन और क्लासेन की 27 गेंद में नाबाद 53 रन की पारी के दम पर सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए छह विकेट पर 197 रन बनाए जो मौजूदा सत्र में इस मैदान का सर्वोच्च स्कोर है। टीम के लिए अब्दुल समद ने 21 गेंद में एक चौका और दो छक्कों की मदद से 28 रन बनाए।

दिल्ली की टीम के लिए मिशेल मार्श का हरफनमौला खेल और फिल साल्ट के साथ दूसरे विकेट के लिए 66 गेंद में 112 रन की साझेदारी नाकाफी साबित हुई और टीम 20 ओवर में छह विकेट पर 188 रन ही बना सकी।

मार्श ने चार ओवर में 27 रन देकर चार विकेट झटकने के बाद 39 गेंद में एक चौका और छक्के की मदद से 63 रन बनाए। साल्ट ने 35 गेंद में 59 रन की पारी में नौ चौके जड़े। आखिरी ओवरों में अक्षर पटेल ने 14 गेंद में एक चौका और दो छक्के की मदद से नाबाद 29 रन की पारी खेली।

इस जीत के साथ ही सनराइजर्स हैदराबाद ने 24 अप्रैल को इस टीम से मिली हार का बदला भी चुकता कर लिया। हैदराबाद के लिए यह आठ मैचों में तीसरी जीत है जबकि दिल्ली के लिए आठ मैचों में यह छठी हार है।

सनराइजर्स के लिए मयंक मार्कंडेय ने चार ओवर में 20 रन देकर दो विकेट चटकाए। भुवनेश्वर कुमार , अकील हुसैन, टी नटराजन और अभिषेक शर्मा को एक-एक सफलता मिली।

लक्ष्य का बचाव करते हुए भुवनेश्वर ने पारी की दूसरी ही गेंद पर डेविड वार्नर को बोल्ड कर सनराइजर्स को अच्छी शुरुआत दिलाई लेकिन फिल साल्ट ने शुरुआती तीन ओवरों में तीन चौके लगाए।

दूसरे छोर से मार्श ने अकील हुसैन और फिर टी नटराजन के खिलाफ छक्का जड़ा। पावरप्ले के बाद दिल्ली का स्कोर एक विकेट पर 57 रन था।

सातवें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए उमरान मलिक का स्वागत साल्ट ने चौके से किया फिर मार्श ने दो छक्के लगाए और आखिरी गेंद पर साल्ट ने एक और चौका लगाकर ओवर से 22 रन बटोरे।

मार्श ने नौवें ओवर में बाएं हाथ के कामचलाऊ गेंदबाज अभिषेक के खिलाफ लगातार गेंदों पर चौका और छक्का लगाया। अगले ओवर में मयंक मार्कंडेय पर चौके के साथ साल्ट ने 29 गेंद में आईपीएल का अपना पहला अर्धशतक और मार्श के साथ 54 गेंद में शतकीय साझेदारी पूरी की।

अतंरराष्ट्रीय

NASA ने चंद्रमा की मिट्टी से निकाली ऑक्सीजन, वैज्ञानिकों ने बताया मील का पत्थर

वाशिंगटन। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा अपने आर्टमिस मिशन के जरिए अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने की तैयारी में है। इस मिशन के जरिए नासा का असली मकसद चंद्रमा की सतह पर अपनी दीर्घकालिक मौजूदगी बनाए रखना है। इस मकसद को वास्तविकता बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ऑक्सीजन का निर्माण है। ऑक्सीजन का इस्तेमाल सांस लेने के अलावा ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रोपेलैंट के रूप में भी किया जा सकता है। इससे चंद्रमा पर पहुंचने वाले

अंतरिक्ष यात्रियों को लंबे समय तक रहने और आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इसी बीच एक परीक्षण के दौरान ह्यूस्टन में नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर के वैज्ञानिकों ने सिमुलेटेड चंद्रमा की मिट्टी से सफलतापूर्वक ऑक्सीजन निकाली है। चंद्रमा की मिट्टी का अर्थ सतह को ढकने वाली सूक्ष्म सामग्री से है। ऐसा पहली बार हुआ है, जब चंद्रमा की मिट्टी से ऑक्सीजन को एक निर्यात वातावरण में निकाला गया है। इस ऑक्सीजन की मात्रा इतनी है कि इससे चंद्रमा की सतह पर मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों की एक दिन की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा वहां मौजूद दूसरे संसाधनों के उपयोग में भी मदद कर सकता है। इसे इन-सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है।

नासा की कार्बोथर्मल रिडक्शन डिमॉन्स्ट्रेशन (सीएआरडी) टीम ने डर्टी थर्मल वैक्यूम चैंबर नाम के 15 फुट गोलाई वाले एक स्पेशल गोलाकार चेंबर का इस्तेमाल करके चंद्रमा पर पाए जाने वाली परिस्थितियों का निर्माण किया।

बलूचिस्तान में मंकीपॉक्स को लेकर स्कूलों में हाई अलर्ट

क्वेटा (वार्ता)। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मंकीपॉक्स के मामले सामने आने के बाद इसके संक्रमण को लेकर स्कूलों को हाई अलर्ट किया गया है।

प्रांतीय शिक्षा निदेशालय ने एक अधिसूचना में जिला शिक्षा अधिकारियों और प्रधानाचार्यों को वायरल संक्रमण (मंकीपॉक्स) के प्रसार पर नियंत्रण के लिए समुचित और त्वरित कार्रवाई तथा निवारक उपाय करने के लिए कहा है। अगर किसी में इसके लक्षण पाए जाते हैं, तो उन्हें किसी अस्पताल से संपर्क करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही ऐसे छात्र या व्यक्ति को दूसरों से दूर रखने का निर्देश दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि इस हफ्ते की शुरुआत में पाकिस्तान में विदेश से देश की यात्रा करने वाले दो लोग मंकीपॉक्स से ग्रसित पाये गये थे। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, मंकीपॉक्स के रोगी को सऊदी अरब से निर्वासित किया गया था और 17 अप्रैल को मंकीपॉक्स के लक्षणों के साथ पाकिस्तान में उतरा था। इसी बीच फ्लाइट में उनके साथ बैठे एक अन्य व्यक्ति में भी एमपॉक्स के लक्षण दिखे।

इस बीच डब्ल्यूएचओ ने पाकिस्तान को मंकीपॉक्स वायरस से निपटने में सहायता का आश्वासन दिया। संगठन ने एक बयान में कहा कि वह पाकिस्तान की सरकार के साथ मिलकर वायरस के प्रसार की जांच कर रहा है। डब्ल्यूएचओ ने सरकार को विशेष रूप से प्रयोगशाला परीक्षण प्रक्रिया, प्रवेश के बिंदु और परीक्षण किट प्रदान करने में सहायता का आश्वासन दिया है।

ईरान, इराक के नेताओं ने सहयोग को मजबूत करने का लिया संकल्प

तेहरान, (वार्ता) ईरान के सर्वोच्च नेता श्री अली खमेनेई ने राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी और इराक के राष्ट्रपति अब्दुल लतीफ राशिद के साथ बातचीत में दोनों देशों के बीच सहयोग का विस्तार पूर्व में हस्ताक्षरित द्विपक्षीय समझौतों पर क्रियान्वयन द्विपक्षीय पक्षों के हितों को पूरा करता है।

श्री खमेनेई ने दोनों नेताओं के साथ हुयी एक बैठक में यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इराक की प्रगति और समृद्धि ईरान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए ईरान इराक के साथ हमेशा खड़ा रहेगा और इसे और प्रगति करते देखना चाहता है।

उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच एकता बाहरी राजनीतिक कारकों से प्रभावित नहीं हो सकती है इसलिए हमें द्विपक्षीय संबंधों की रक्षा करनी चाहिए और इसे आगे बढ़ाने के लिए मिलकर प्रयास करना होगा।

छोटी खबरें

अवैध बूचड़खानो पर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई

उत्तराखंड प्रहरी ब्यूरो

हरिद्वार। बहादराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत प्रचलित चार धाम यात्रा के दृष्टिगत रविवार को एसएसपी हरिद्वार के आदेशानुसार अवैध कार्यों में लिप्त लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सख्त आदेश के क्रम में थाना बहादराबाद के चौकी शांतरशाह क्षेत्र में मांस मछलियों की दुकानों की चेकिंग की गई जिसमें 15 दुकानों में खामियां पाई गई

जिनके विरुद्ध पुलिस अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई जिसमे कुल 15 लोगों के चालान करके ₹1,50,000 की वसूली की गई।यह कार्यवाही अवैध बूचड़खाने में अन्य अपराधिक क्रियाकलाप करने की शिकायत प्राप्त होने पर की गई है सभी दुकानों के स्वामियों को दुकानों में सीसीटीवी कैमरा लगाये जाने, माल के लाने ,ले जाने का अध्वाधिक रजिस्टर तैयार करने एवं बिना लाइसेंस के कोई भी दुकान न चलाने की हिदायत दी गई।

देशी-विदेशी जोड़े उत्तर प्रदेश के किलों और महलों में भी जल्द रचा सकेंगे शादी

लखनऊ। राजस्थान के महलों में देशी-विदेशी जोड़ों की शादियों (डेस्टिनेशन वेडिंग) से होने वाली भारी आय को देखते हुए अब उत्तर प्रदेश सरकार भी राज्य के प्रसिद्ध किलों, महलों और ऐतिहासिक स्थलों को वैवाहिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर कमाई करने की तैयारियों में जुट गई है। उत्तर प्रदेश को 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के तहत नई पर्यटन नीति-2022 में इस तरह की पहल की गई है और बहुत जल्द मंत्रिमंडल की बैठक में भी इस संबंध में प्रस्ताव लाए जाने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव (पर्यटन एवं संस्कृति) मुकेश कुमार मेश्राम ने पीटीआई-भाषा से कहा, उत्तर प्रदेश में राजसी ठाठ-बाट और सांस्कृतिक विरासत के जरिए शादी को यादगार बनाने वाले बहुत ही आकर्षक स्थल मौजूद हैं। आगरा का ताजमहल जहां प्यार का प्रतीक है, वहीं मथुरा-वृंदावन को आध्यात्मिक प्रेम की नगरी माना जाता है। उन्होंने कहा, चुनार किले से लेकर बाजीराव-मस्तानी के अगाध प्रेम से जुड़ा महोबा का मस्तानी महल और बुंदेलखंड के विभिन्न किले भी लोकप्रिय डेस्टिनेशन वेडिंग के रूप में उभर सकते हैं। हम इन महलों और किलों को वैवाहिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने जा रहे हैं, ताकि लोग प्रेम की अटूट गाथा के गवाह स्थलों पर वैवाहिक बंधन में बंध सकें।

एक अधिकारी ने बताया, राजस्थान में नवंबर 2022 से मार्च 2023 के बीच लगभग 40 हजार डेस्टिनेशन वेडिंग हुईं। प्रदेश में एक सत्र में इस तरह की शादियों से औसतन 2,500 करोड़ रुपए का कारोबार होता था, जो कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित हुआ था। हालांकि, अब यह धीरे-धीरे पटरी पर लौटने लगा है। पर्यटन विभाग का आकलन है कि बड़ी संख्या में देशी-विदेशी पर्यटक अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए आगरा और वाराणसी आते रहे हैं, लेकिन कोविड-19 की दस्तक के बाद से प्रदेश में विदेशी पर्यटकों की आमद कम हो गई है और डेस्टिनेशन वेडिंग का आकर्षण भी घटा है। प्रमुख सचिव ने बताया, अब स्थिति सामान्य हो रही है।

‘मन की बात’ से पीएम मोदी कई अनछुए पहलुओं को रखते है देश के सामने: कुसुम कण्डवाल

मोदी जी के मन की बात अनेकों असाधारण देशवासियों का मनोबल बढ़ाते हुए देती है प्रेरणा: कुसुम कण्डवाल

उत्तराखंड प्रहरी ब्यूरो

देहरादून। डोईवाला के भानियावाला में स्थित सिद्धिविनायक वेडिंग पॉइंट में आयोजित माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात के इस 100वें संस्करण को राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने वार्ड नंबर 10 में विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्वयं सहायता समूहों की बहनों के साथ सुना।

इस अवसर पर उन्होंने वहां उपस्थित लोगों से कहा कि यह आज गर्व का विषय है की हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मन की बात के 100वें संस्करण का प्रसारण संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में भी किया गया है यह दिखलाता है की आज भारत सम्पूर्ण विश्व की वसुधैव कुटुंबकम्-की सभ्यता के साथ अगुवाई रहा है। आज विश्व भर में भी प्रवासी भारतीयों ने भी प्रधानमंत्री जी के ‘मन की बात’ के इस 100 वें संस्करण को सुना है। उन्होंने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम में अब तक 500 से अधिक देशवासियों से इस कार्यक्रम के माध्यम से बात की है, जो असाधारण

काम कर रहे हैं। उनका मनोबल बढ़ाने का और उनसे अनेको लोगो को प्रेरणा देने का काम में कई बात कार्यक्रम के माध्यम से हो रहा है। कार्यक्रम के अंत मे उन्होंने सभी को बधाई देते हुए कहा कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते है कि हम वर्षो वर्षों तक माननीय प्रधानमंत्री को सुनते रहे और उनका मार्गदर्शन देश को मिलता रहे।

मनोज सिन्हा ने जम्मू में मैराथन को हरी झंडी दिखाई

जम्मू। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी के प्रसारण के उपलक्ष्य में यहां एक मैराथन को हरी झंडी दिखाई। मन की बात कार्यक्रम का जश्न मनाने के लिए हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स और डोगरा क्रांति दल द्वारा आयोजित यह मैराथन केंद्र-शासित प्रदेश में इस अवसर पर दिनभर में प्रस्तावित 100 मैराथन में से एक थी। उन्होंने बताया कि यहां बलिदान स्तंभ (युद्ध स्मारक) पर मैराथन को हरी झंडी दिखाने से पहले सिन्हा ने कहा, केंद्र-शासित प्रदेश में आयोजित होने वाली सभी 100 मैराथन जागरूकता भी बढ़ाएंगी और मादक पदार्थ के सेवन तथा तस्करी के खिलाफ कार्वाई और सहयोग को भी मजबूत करेंगी। उपराज्यपाल ने कहा कि मादक पदार्थ के खतरे से लडने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के लोग एक साथ आए हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने मन की बात के माध्यम से देश के युवाओं को चुनौतियों से पार पाने और जीवन में एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया है।

देहरादून विदाई समारोह’ उप अधीक्षक नीरज सेमवाल द्वारा स्मृति चिन्ह देकर अधिकारियों को दी यादगार विदाई

उत्तराखंड प्रहरी ब्यूरो

देहरादून। नीरज सेमवाल पुलिस उपाधीक्षक नगर महोदय की उपस्थिति में पुलिस लाइन देहरादून में जनपद देहरादून से माह अप्रैल में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी/कर्मचारीगणों के सेवानिवृत्ति पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया विदाई समारोह के दौरान अपने सम्बोधन में महोदय द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी/कर्मचारीणों के सेवानिवृत्ति के पश्चात अच्छे स्वास्थय व दीर्घायु कि कामना करते हुए उन्हें शाल, स्मृति चिहन तथा उपहार देकर भावभीनी विदाई दी गयी तथा अपेक्षा की कि भविष्य में भी पुलिस को उनके अनुभवों का लाभ व मार्ग दर्शन मिलता रहेगा।

- 01-सुरेन्द्र सिंह , उप निरीक्षक ना0पु0, इनका सेवाकाल कुल 41 वर्ष 01 माह 15 दिवस का रहा। सेवाकाल के दौरान इनके द्वारा 43 पीएसी एटा, जनपद पौड़ी, 40 पीएसी तथा जनपद देहरादून में अपनी सेवायें प्रदान की गयी।
- 02-गोविंद सिंह ,अपर उप निरीक्षक, नापु० , इनका सेवाकाल कुल 40 वर्ष 11माह 15 दिवस का रहा। सेवाकाल के दौरान इनके द्वारा जनपद चमोली, पौड़ी, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी तथा जनपद देहरादून में अपनी सेवायें प्रदान की गयी।
- 03-जगदीश सिंह बिष्ट, मुख्य आरक्षी ना0पु० (भूतपूर्व सैनिक) इनका सेवाकाल कुल 21 वर्ष, 06 माह 20 दिवस का रहा। सेवाकाल के दौरान इनके द्वारा जनपद हरिद्वार तथा जनपद देहरादून में अपनी सेवायें प्रदान की गयी।

विदाई समारोह में जगदीश चन्द्र पंत, प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन देहरादून, सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के परिजनों के अतिरिक्त पुलिस परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे।

उत्तर प्रदेश: मध्याह्न भोजन में बच्चों को बाजरे की रोटी और खिचड़ी दिए जाने की तैयारी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों के छात्रों को बेहतर पोषण के लिए सरकार ने सप्ताह में कम से कम एक बार बाजरे की रोटी और खिचड़ी देने की तैयारी की है, जिसकी शुरुआत जल्द हो सकती है।

वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। इस संबंधी प्र स्ताव भारत सरकार ने पेश किया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र और एफएओ (खाद्य और कृषि संगठन) शासी निकाय के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया गया था।

उत्तर प्रदेश में स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने पीटीआई-भाषा से कहा, मध्याह्न भोजन में मोटे अनाज को शामिल करने के संबंध में हम जल्द ही केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।

कक्षा एक से आठ तक के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार उत्तर प्रदेश के मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव दिया है कि राज्य भर के 1.42 लाख स्कूलों में छात्रों को मोटा अनाज आधारित भोजन परोसा जाए। योजना के मुताबिक, मध्याह्न भोजन में छात्रों को बाजरे की रोटी या खिचड़ी परोसी जाएगी। इसके साथ सब्जी या मूंग की दाल दी जाएगी। इसके लिए मध्याह्न भोजन प्राधिकरण को अनुमानित 62,000 टन मोटा अनाज खरीदने की जरूरत है। वर्तमान में सप्ताह में छह दिन बच्चों को सब्जियों या प्रोटीन के साथ गेहूं या चावल से बने व्यंजन परोसे जाते हैं।

उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने हाल में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में बाजरा को शामिल करने की योजना की घोषणा की थी। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए बाजरा उपलब्ध कराने के वास्ते राज्य सरकार ने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को एक प्रस्ताव भी भेजा है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा कि अगर केंद्र सरकार द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जाती है और आवश्यक मात्रा में खरीद की जाती है, तो गर्मियों की छुट्टियों के बाद योजना जल्द ही लागू हो जाएगी। अभी तक उत्तर प्रदेश में मध्याह्न भोजन का कुल बजट लगभग 3,000 करोड़ रुपए है। केंद्र सरकार लागत का 60 प्रतिशत वहन करती है और शेष राज्य द्वारा वहन किया जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार, बाजरा पोषक तत्वों के साथ-साथ आवश्यक यौगिकों से भरपूर होता है और गेहूं या चावल की तुलना में बेहतर भोजन विकल्प माना जाता है। लखनऊ में रहने वाली आहार विशेषज्ञ पूर्णिमा कपूर ने कहा, फिलहाल मोटा अनाज हमारे घरों में भोजन के रूप में अकसर नहीं खाया जाता है।

हरिद्वार जिले में 794 बूथों पर सुनी गई मन की बात

उत्तराखंड प्रहरी ब्यूरो

हरिद्वार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए जाने वाले जनसंवाद कार्यक्रम मन की बात का 100 वा संस्करण प्रसारित किया गया। हरिद्वार जिले में 794 बूथों पर आज यह ऐतिहासिक कार्यक्रम सुना गया हरिद्वार में प्रमुख रूप से शांतिकुंज, पतंजलि, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हर की पौड़ी, एसएम जैन डिग्री कॉलेज, सिडकुल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, नारायण सेवा संस्थान ,दिव्य प्रेम सेवा मिशन, कुष्ठ आश्रम चंडी घाट एवं ऋषि कुल ऑडिटोरियम में संत समाज ने कार्यक्रम सुना।

आज का यह कार्यक्रम कई मायनों में ऐतिहासिक एवं अविस्मरणीय रहा किसी भी राजनेता द्वारा जनता से संवाद का निरंतर चलने वाला यह एकमात्र कार्यक्रम है यह कार्यक्रम इसलिए ही अविस्मरणीय है क्योंकि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीतिक विषयों से अलग सिर्फ सामाजिक सरोकार एवं जनता के बीच छिपे अनाम नायकों को समाज के सामने लाने का कार्य कर रहे हैं हरिद्वार जनपद में यह कार्यक्रम 816 में से 794 बूथों पर आयोजित किया गया जिनमें से लगभग 500 बूथों पर प्रत्येक पर 100 से अधिक संख्या द्वारा यह कार्यक्रम सुना गया जिनमें प्रमुख रूप से शांतिकुंज में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में डॉ चिन्मय पंड्या के नेतृत्व में 15

00 से ज्यादा संख्या में साधकों, शिक्षकों एवं छात्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात को सुना। इस अवसर पर जिला महामंत्री आशुतोष शर्मा भी शांतिकुंज में उपस्थित रहे।

हर की पौड़ी पर हजारों लोगों की उपस्थिति में मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण सुना गया जिसमें प्रमुख रुप से जिलाध्यक्ष भाजपा संदीप गोयल स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि कन्हैया खेवरिया, उप जिला अधिकारी पूर्ण सिंह राणा, बूथ अध्यक्ष मनोज कुमार व गंगा सभा के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। ऋषि कुल ऑडिटोरियम में हरिद्वार के समस्त संत समाज ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद डॉ रमेश पोखरियाल निशंक के साथ भारी संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों को सुना इस अवसर पर मन की बात के जिला संयोजक लव शर्मा ,सांसद प्रतिनिधि ओमप्रकाश जमदग्नि, जिला सोशल मीडिया प्रभारी मनोज शर्मा, पूर्व राज्यमंत्री पंकज सहगल ,राजन मेहता, विमल कुमार, अनिल अरोड़ा, वीरेंद्र सिंह, मनोज गौतम आदि उपस्थित रहे।

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में विश्वविद्यालय के प्रोफेसर व अन्य कर्मचारियों ने सैकड़ों की संख्या में मन की बात कार्यक्रम को सुना इस कार्यक्रम के संयोजक मंडल अध्यक्ष नागेंद्र राणा रहे।

सिडकुल के उद्योगपतियों एवं स्थानीय नागरिकों द्वारा होटल गार्डेनिया के सभागार में नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा के संयोजन में आयोजित मन की बात कार्यक्रम को सुना।

पतंजलि योगपीठ में भी शोधकर्ता वैज्ञानिकों एवं साधकों द्वारा भारी संख्या में मन की बात कार्यक्रम को सुना गया।

इस प्रकार से मन की बात कार्यक्रम का 100वा प्रसारण हरिद्वार जनपद के समस्त प्रमुख संस्थानों में सुना व देखा गया।

जन आंदोलन बन चुका है पीएम का मन की बात कार्यक्रम : मदन कौशिक

उत्तराखंड प्रहरी ब्यूरो

हरिद्वार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के सौ एपिसोड पूरे होने पर नगर विधायक मदन कौशिक के संयोजन में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ज्वालापुर स्थित एक बेंकट हॉल में आयोजित कार्यक्रम में चिकित्सा, शिक्षा, वकालत आदि क्षेत्रों से जुड़े प्रबुद्ध लोगों ने पीएम की मन की बात सुनी। इस अवसर पर विधायक मदन कौशिक ने कहा कि पीएम मोदी देश के विकास की गति तेज करने के साथ लोगों को प्रेरित करने में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री देश के लोगों से सीधा संवाद स्थापित करते हैं। जिससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि पीएम का मन की बात कार्यक्रम एक जनांदोलन बन चुका है। मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री समाज के प्रत्येक वर्ग को छूते हैं। प्रत्येक आयु वर्ग के लोग मन की बात कार्यक्रम का इंतजाम करते हैं। डा.विशाल गर्ग ने

ऐतिहासिक रहा मन की बात का सौंवा ऐपिसोड:डा. ववशाल गर्ग

कहा कि मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। मन की बात के अब तक सभी एपिसोड में प्रधानमंत्री ने अलग-अलग विषयों को लिया और लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। विधायक प्रतिनिधि एडवोकेट राजकुमार अरोड़ा एवं भाजपा मंडल उपाध्यक्ष सिद्धार्थ कौशिक ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का मन की बात कार्यक्रम सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम है। देश दुनिया में मन की बात पर चर्चाएं होती हैं। प्रधानमंत्री देश के विकास में जनता के योगदान की चर्चा करते हैं तो लोगों में देश के प्रति जिम्मेदारी का अहसास बढ़ता है। डा.राम शर्मा व डा.संध्या शर्मा ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम का सौंवा ऐपिसोड ऐतिहासिक है।

मन की बात की लोकप्रियता से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से जनता से जुड़ती है। इस अवसर पर डा.अंशुल श्रीमाली, डा.राम शर्मा, डा.सुशील शर्मा, डा.विशाल गर्ग, डा.जितेंद्र चंदेला, डा.दिनेश सिंह, डा.माधवी अग्निहोत्री, डा.नेहा, डा.राजसिंह चैहान, डा.कुमार प्रशांत, विधायक प्रतिनिधि एडवोकेट राजकुमार कुमार अरोड़ा, पारूल चैहान, आशा शर्मा, दिनेश पांडेय, मृदुला सिंघल, मनीष, गजेंद्र, राजेंद्र कटारिया, सपना शर्मा, पदम प्रकाश शर्मा, देशराज शर्मा सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल रहे।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक/संपादक- विकास गर्ग ने भगवती प्रिंटिंग प्रेस, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार उत्तराखंड से मुद्रित करवाकर 54 आवास विकास, विवेक विहार, रानीपुर मोड़, हरिद्वार उत्तराखंड से प्रकाशित किया।
प्रकाशक / संपादक : विकास गर्ग- फोन : 9897766448, : मुख्य संपादक / सुमित तिवारी- फोन : 8077771906 : Email : uttarakhandprahari19@Gmail.com